राजस्थान में फूड प्रोसेसिंग, स्पाइस पार्क व एग्री एक्सपोर्ट की अपार सभावनाएँ- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने जयपुर में होने वाले ग्राम 2026 में आमंत्रित करने के लिए दिल्ली में इन्वेस्टर मीट को संबोधित किया

नई दिल्ली/जयपुर, 23 अप्रेल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जयपुर में 23 से 25 मई तक "ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट" (ग्राम)-2026 का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत किसानों, कृषि विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और निवेशकों को एक मंच पर लाकर कृषि प्रौद्योगिकी के

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बाजरा, सरसों, तिलहन, जौ, ग्वार, ईसबगोल व जीरे के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। दलहन उत्पादन के लिए झालावाड़ व टोंक को मॉडल जिले के रूप में विकसित किया जा रहा है।**

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित ग्राम-2026 इन्वेस्टर मीट को संबोधित किया।

माध्यम से किसानों की मजबूती पर बल दिया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी निवेशकों एवं उद्यमियों को ग्राम-2026 में भाग लेने का आमंत्रण भी दिया।

मुख्यमंत्री गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित ग्राम-2026 इन्वेस्टर मीट को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 'ग्राम' के तहत, गिरदावर सर्किल, उपखण्ड, जिला सहित प्रत्येक स्तर पर गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा किसान लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा कि राजस्थान कृषि उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है। बाजरा, सरसों, तिलहन, जौ, ग्वार, ईसबगोल और जीरे के उत्पादन में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है।

इस विविधता से फूड प्रोसेसिंग, स्पाइस पार्क और एग्री-एक्सपोर्ट जैसे क्षेत्रों में उद्यमियों के लिए अपार संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार उद्यमियों को निवेश अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कर कृषि क्षेत्र में करीब 44 हजार करोड़ रुपये के एमओयू साइन किए गए, जिनमें से 9 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश धरातल पर उतर भी चुका है। ग्राम-2026 इसी निवेश यात्रा को और आगे ले जाने का मंच है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पहली बार पश्चिम क्षेत्रीय जोनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। दलहन उत्पादन के मामले में झालावाड़ व टोंक जिलों को मॉडल जिलों के तौर पर विकसित किया जा रहा है।

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट के तहत अहमदाबाद, हैदराबाद एवं पुणे सहित, देश के कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। देश के कृषकों को नई तकनीकों की जानकारी देने के लिए आयोजित ग्राम एकीकृत अंतर्राष्ट्रीय मंच है, जहां नीति निर्माता, वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञ शामिल होंगे।

अधिकार बचाने के लिये लोगों ने बम्पर मतदान किया -ममता

कोलकाता, 23 अप्रैल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण में शाम पांच बजे तक लगभग 90 प्रतिशत मतदान दर्ज होने के बाद तृणमूल कांग्रेस प्रमुख व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे जनता के अधिकारों की लड़ाई से जोड़ते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में भारी मतदान इसलिए हो रहा है, क्योंकि लोग अपने अधिकार, पहचान और भविष्य की रक्षा के लिए मतदान केन्द्रों तक पहुंच रहे हैं। चौरंगी क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी नयना बंद्योपाध्याय के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि जनता समझ चुकी है कि यह सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि अधिकार बचाने की लड़ाई है। उन्होंने दावा किया कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए थे, जिनमें से लाखों नाम कानूनी लड़ाई के बाद फिर से जुड़वाए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग जानते हैं कि यदि उनके अधिकारों की रक्षा नहीं हुई तो संपत्ति, पहचान, पता और रोजगार तक पर संकट आ सकता है।

एसओजी ने फ़र्ज़ी डिग्री तैयार करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया

जयपुर, 23 अप्रैल। राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) द्वारा आयोजित प्राध्यापक-हिन्दी (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा-2022 में फर्जी डिग्री के जरिए नौकरी पाने की कोशिश करने वाले गिरोह के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने फर्जी डिग्री तैयार करने और करवाने में मुख्य भूमिका निभाने वाले आरोपी ध्वज कीर्ति शर्मा को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ मिलकर अभ्यर्थियों को फर्जी अंकतालिकाएं और डिग्रियां बांटी थीं। फिलहाल आरोपित से पूछताछ की जा रही है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस (एसओजी) विशाल बंसल ने बताया कि एसओजी ने कार्रवाई करते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) द्वारा आयोजित प्राध्यापक-हिन्दी (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा-2022 में फर्जी डिग्री के जरिए नौकरी दिलाने में सहयोग करने सहित, फर्जी डिग्री तैयार करने और करवाने में मुख्य भूमिका निभाने वाले आरोपी ध्वज कीर्ति शर्मा (55) निवासी गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ को गिरफ्तार किया है।

- **आरोपी ध्वज कीर्ति शर्मा पर पूर्व में भी विभिन्न विश्वविद्यालयों की फ़र्ज़ी डिग्रियाँ जारी करने के कई प्रकरण दर्ज हैं।**

आरोपी शातिर जालसाज है। उसके खिलाफ पूर्व में भी विभिन्न विश्वविद्यालयों की फर्जी डिग्रियां जारी करने के कई प्रकरण दर्ज हैं। वह लंबे समय से शिक्षा जगत में इस तरह के फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहा था।

विशाल बंसल ने बताया कि अभ्यर्थी कमला कुमारी ने पात्रता जांच के दौरान मेवाड़ यूनिवर्सिटी गंगरार (चित्तौड़गढ़) की एमए (हिन्दी) की डिग्री पेश की थी। आयोग ने जब इस डिग्री का विश्वविद्यालय से सत्यापन कराया तो सामने आया कि ऐसी कोई डिग्री वहां से जारी ही नहीं हुई है। इसके बाद मार्च 2023 में अजमेर के सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज किया गया था, जिसकी जांच एसओजी कर रही है। जांच में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार आरोपी ध्वज कीर्ति शर्मा ने मेवाड़ यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट/प्रो-प्रेसिडेंट कौशल किशोर चंद्रुल, सुशील कुमार शर्मा, उप परीक्षा नियंत्रक, कार्यालय सहायक राजेश सिंह राणावत और वीरेन्द्र सिंह के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र रचा। जहां आरोपी ध्वज कीर्ति ने फर्जी माइग्रेशन सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र और डिग्री पर डीन व रजिस्ट्रार की फर्जी सील लगाकर स्वयं के हस्ताक्षर किए थे। मुख्य आरोपी ध्वज कीर्ति शर्मा को प्रोडक्शन वारंट पर प्राप्त कर औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया। पुलिस रिमांड के दौरान उससे अन्य फर्जी डिग्रियों और इस गिरोह के अन्य नेटवर्क के बारे में पूछताछ की जा रही है।

गौरतलब है कि इस हाई-प्रोफाइल मामले में फर्जी डिग्री प्राप्त करने वाली मुख्य अभ्यर्थी कमला कुमारी सहित दस आरोपितों को पुलिस पहले ही सलाखों के पीछे भेज चुकी है।

'ईरान से अमेरिकन जहाज पीछे हटेंगे'

अमेरिका ने बड़ी घोषणा की और नाकाबंदी कर रहे जहाजों को पीछे हटने का आदेश दिया

वाशिंगटन/तेहरान, 23 अप्रैल। ईरान के बंदरगाहों की नाकाबंदी के बीच अमेरिका ने बड़ी घोषणा की है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने बुधवार रात कहा कि नाकाबंदी में शामिल अमेरिकी सेना के दो और जहाजों को वापस लौटने (पीछे हटने) का निर्देश दिया गया है।

इस नाकाबंदी के तहत अब तक कुल 31 जहाजों को वापस लौटने को कहा गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले संघर्ष विराम बढ़ाने की भी घोषणा कर चुके हैं। बावजूद इसके, ईरान बातचीत की मेज पर नहीं लौटा है। उसने कहा कि उसे राष्ट्रपति ट्रंप की बात पर भरोसा नहीं है। इस गतिरोध के बीच ईरान को पाकिस्तान मनाने की कोशिश कर रहा है। उधर, इज़रायल के हमले में लेबनान की महिला पत्रकार की मौत हो गई है।

अल जजीरा और सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के खिलाफ 13 अप्रैल से की गई अमेरिकी नाकाबंदी में 10,000 से अधिक अमेरिकी सैनिक, 17 युद्धपोत और 100 से अधिक विमान शामिल हैं। कमांड के अनुसार, नाकाबंदी कर रहे अधिकांश जहाज वर्तमान में ईरानी बंदरगाह चाबहार में खड़े हैं। ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों ने शांति वार्ता में आई रुकावट के लिए वाशिंगटन को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि देश के बंदरगाहों की नौसैनिक घेराबंदी के कारण ऐसा हुआ है।

- **अब तक कुल 31 जहाजों को पीछे लौटने के लिए कहा गया है।**

ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड का कहना है कि उसने होर्मुज़ जलडमरूमध्य में दो विदेशी जहाजों को अपने कब्जे में ले लिया और समुद्री नियमों का उल्लंघन करने पर तीसरे जहाज पर गोलीबारी की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा कि तेहरान "बातचीत और समझौते" का इच्छुक है, लेकिन "वादों का उल्लंघन, घेराबंदी और धमकी ही सच्ची बातचीत में मुख्य बाधा हैं।"

व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलीन लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ अपने संघर्ष विराम को बढ़ाने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की है। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रपति का ही फैसला होगा कि यह संघर्ष विराम कब समाप्त होगा। उधर, लेबनान ने पत्रकार अमल खलील की लक्षित हत्या के लिए इज़रायल की निंदा की है। यह घटना दोनों देशों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते के बीच हुई है।

एसीडी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

यह आदेश आरके मीणा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता अजातशत्रु मीणा और मोविल जीनवाल ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने साल 2022-23 की एसई पद पर पदोन्नति को लेकर याचिका दायर की थी, जिसमें कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 1 अप्रैल, 1997 से रोस्टर रजिस्टर रखना जरूरी है। इसके बावजूद, डिस्कॉम बिना रोस्टर रजिस्टर रखे पदोन्नतियां कर रहा है। वहीं याचिका दायर करने के बाद याचिकाकर्ता को पदोन्नति से वंचित करने के लिए तीन आरोप पत्र दिए गए। जिस पर जांच कर जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी। इस जांच रिपोर्ट पर डीपीसी की चेयरपर्सन और अनुशासनात्मक जांच प्राधिकारी, जो कि सीएमडी भी हैं, ने कोई आदेश पारित नहीं किया और डीपीसी आयोजित कर ली। याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया की पूर्व में अदालत ने सीएमडी से शपथ पत्र पेश कर रोस्टर रजिस्टर संधारित करने की जानकारी मांगी थी, लेकिन रोस्टर रजिस्टर देने के बजाय सारणीबद्ध डेटा ही दिया गया। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने एसीबी को जांच करने के आदेश दिए हैं।

पचास साल में पहली बार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गए अपराधियों को गिरफ्तार करने के निर्देश जारी किए गए। इसके बाद लगभग बीस लोग गिरफ्तार कर जेल में डाल दिए गए। ऐसी घटनाओं पर पहले कभी इस तरह तुरन्त कार्रवाई नहीं हुई थी।

केन्द्रीय बलों की बड़ी संख्या में तैनाती और उनके संचालन की कड़ी निगरानी ने सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति चुनाव प्रक्रिया पर कब्ज़ा न कर सके। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में डेरा डाले हुए हैं, उन्होंने कानून व्यवस्था और स्वतंत्र मतदान की व्यवस्था की निगरानी की।

आज मतदान में शामिल निर्वाचन क्षेत्रों में औसत उपस्थिति 92 प्रतिशत तक पहुंची, जो निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव संचालन के तरीकों के अनुमोदन का संकेत देती है। यहां तक कि अनुभवी राजनीतिक विश्लेषक भी इस उच्च मतदान प्रतिशत को समझाने में कठिनाई महसूस कर रहे थे।

मतदान के असाधारण रूप से उच्च प्रतिशत ने यह स्पष्ट किया कि पहले तृणमूल कांग्रेस ने किस हद तक चुनाव मशीनरी पर कब्ज़ा कर परिणाम अपने पक्ष में बदलने का प्रयास किया था।

असाधारण उच्च मतदान प्रतिशत केवल इस तथ्य से समझाया जा सकता है कि एस आई आर के तहत मतदाता सूची से काल्पनिक, मृत और दोहरी गिनती वाले मतदाताओं को सही तरीके से हटाया गया।

पहले अधिकांश ऐसे मत शासक दलों के पक्ष में डाले जाते थे, क्योंकि वे मतदान केन्द्रों पर कब्ज़ा कर गलत मत डाल सकते थे, जिसमें राज्य पुलिस भी मदद करती थी। इस बार, निर्वाचन आयोग की सफलता इस बात में है कि उसने इस तरह की किसी भी कोशिश को रोकने में सक्रिय भूमिका निभाई।

एसआईआर प्रक्रिया के दौरान ऐसे करीब एक करोड़ काल्पनिक नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पूरी संशोधन प्रक्रिया का अंतिम क्षण तक विरोध किया। जहां अधिकांश राजनीतिक दलों ने गुरुवार के मतदान का स्वागत किया, वहीं तृणमूल कांग्रेस ने आम तौर पर इसका विरोध किया।

अमित शाह ने चुनाव सभाओं में ममता बनर्जी पर निशाना साधा

कोलकाता, 23 अप्रैल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को हुगली जिले के बलागढ़ और पुरशुरा की चुनावी सभाओं से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। शाह ने दावा किया कि पांच मई के बाद राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और तृणमूल शासन समाप्त हो जाएगा। बलागढ़ की सभा में अमित शाह ने कहा, ममता को टाटा-बाय बाय करो, सिंडिकेटबाजों को उल्टा करके सीधा किया जाएगा।

तमिलनाडु व ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सुनिश्चित करने के लिए, आयोग ने 5,011 फ्लाइंग स्क्वॉड टीमों को तैनात किया है, जिनमें 2,728 पश्चिम बंगाल और 2,283 तमिलनाडु में हैं। इन टीमों को शिकायतों पर प्रतिक्रिया 100 मिनट के भीतर देने का कार्य सौंपा गया है। इसके अलावा, 5,363 स्टैटिक सर्विलांस टीमों को दोनों राज्यों में तैनात किया गया है, जो अचानक जांच करती हैं और प्रमुख स्थानों पर नाके स्थापित करती हैं।

पिछले चुनावों से तुलना करने पर वर्तमान कार्यवाही का पैमाना स्पष्ट होता है। पश्चिम बंगाल में 2021 विधानसभा चुनावों के दौरान कुल जब्तियाँ 339.45 करोड़ रुपये और 2024 लोकसभा चुनावों में 450.64 करोड़ रुपये थीं। इन चुनावों ने इन दोनों आंकड़ों को पहले ही पार कर लिया है।

इसी प्रकार, तमिलनाडु में 2021 विधानसभा चुनावों में 446.28 करोड़ रुपये की जब्तियाँ हुईं और 2024 लोकसभा चुनावों में 555.44 करोड़ रुपये की। वर्तमान 599.24 करोड़ रुपये की कुल राशि राज्य में अब तक की सबसे बड़ ज़ब्ती है।

निर्वाचन आयोग ने प्रवर्तन एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया है कि सामान्य जनता को जांच और जब्ती के दौरान असुविधा न हो। शिकायतों को सुलझाने के लिए जिला शिकायत समितियों (डिस्ट्रिक्ट ग्री वैंस कमेटीज़) का गठन भी किया गया है।

आई पैक ऑफिस में ईडी की रेड पर सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस

ईडी के वकील सॉलिसिटर जनरल और तुषार मेहता ने कहा राज्य में कानून का शासन खत्म हो गया

नई दिल्ली, 23 अप्रैल। उच्चतम न्यायालय में आई-पैक के दफ्तर में रेड मामले पर सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के बीच जोरदार बहस हुई। एक तरफ ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य में कानून का शासन पूरी तरह खत्म हो चुका है तो वहीं पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने कोर्ट की टिप्पणियों के राजनीतिक इस्तेमाल पर आपत्ति जताई।

- **राज्य सरकार की वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा, एक राजनैतिक दल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहा है।**

सुनवाई के दौरान, मेनका गुरुस्वामी ने सोशल मीडिया पर एक राजनीतिक दल द्वारा सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को चुनाव प्रचार के हथियार के रुप में इस्तेमाल का आरोप लगाया। उन्होंने तुषार मेहता के लहजे पर भी सवाल उठाया। तब मेहता ने कहा कि वे किसी के इशारे पर नहीं, बल्कि तथ्यों पर आधारित कानूनी दलीलें दे रहे हैं। मेहता ने कहा कि पश्चिम बंगाल में एक खास पैटर्न के तहत जांच को बाधित किया जा रहा है।

मेहता ने कहा कि 8 जनवरी को कोयला तस्करी मामले की जांच के दौरान दस ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, जिसमें प्रतीक जैन का आवास भी शामिल था। ईडी के मुताबिक, अवैध कोयला खनन से मिले 20 करोड़ रुपये की रकम हवाला के जरिये आई पैक को ट्रांसफर की गई। मेहता ने कहा कि छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सैकड़ों पुलिसकर्मियों के साथ दोपहर में परिसर में घुस गईं। मुख्यमंत्री ने ईडी अधिकारियों से जबरन डिजिटल उपकरण और दस्तावेज छीन लिए और कंप्यूटर सिस्टम का बैकअप रोक दिया। इस मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उच्चतम न्यायालय से ईडी की याचिका खारिज करने की मांग की है।

राज्य सरकार की ओर से दाखिल हलफनामा में कहा गया है कि जब इसी तरह की याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय में लंबित है तो समानांतर कार्रवाई नहीं हो सकती है। हलफनामा में कहा गया है कि ईडी को उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दाखिल करने का अधिकार नहीं है। आई पैक के दफ्तर पर सर्च से पहले कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। राज्य सरकार ने ईडी पर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के उल्लंघन का आरोप लगाया है।

'होर्मुज़ नहीं खुला तो 3 करोड़ लोग गरीबी की चपेट में आ सकते हैं'

संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी कि भले ही युद्ध खत्म हो जाए, पर इसका असर लम्बे समय तक रहेगा

न्यूयॉर्क, 23 अप्रैल। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने चेतावनी दी है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से जुड़े मौजूदा संकट का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है, जिससे 03 करोड़ से अधिक लोग गरीबी में धकेले जा सकते हैं। यूएन का कहना है कि भले ही ईरान से जुड़ा संघर्ष तत्काल समाप्त हो जाए, इसके आर्थिक प्रभाव लंबे समय तक बने रहेंगे।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से जुड़े अधिकारी अलेक्जेंडर डी क्रू ने बताया कि इस संकट के चलते वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 0.5 प्रतिशत से 0.8 प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है। इसका सबसे अधिक असर कमजोर और विकासशील देशों पर पड़ने की आशंका है, जहां पहले से ही आर्थिक दबाव बना हुआ है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा कीमतों में तेज वृद्धि और खाद्य असुरक्षा इस संकट के प्रमुख कारण हैं। हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य से न केवल तेल, बल्कि बड़ी मात्रा में उर्वरक भी गुजरता है। ऐसे में इस मार्ग में किसी भी तरह की बाधा से कृषि उत्पादन पर सीधा असर पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, आने वाले महीनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। वर्तमान समय कई देशों में बुवाई का होता है। यदि किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध नहीं हुआ तो सितंबर से नवंबर के बीच फसल उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है। इससे खाद्य संकट गहराने और कीमतों में और बढ़ोतरी होने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में व्यवधान, बढ़ती लागत और आर्थिक अनिश्चितता मिलकर एक व्यापक मानवीय संकट को जन्म दे सकते हैं।

- **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से जुड़े अफसर अलेक्ज़ैंडर डीक्रू ने कहा कि सबसे अधिक असर कमज़ोर और विकासशील देशों पर पड़ेगा।**

अमेरिका में रह रहे 40 प्रतिशत ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भावना में काफी योगदान दिया है। उत्तर देने वालों में से लगभग 71 प्रतिशत ने कहा कि ट्रंप उन्होने अर्थव्यवस्था, आप्रवास और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को जैसे हैंडल किया है, वे उससे नाखुश हैं।

अमेरिका-भारत संबंधों पर कुछ आलोचना की गई है, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए विदेश नीति बड़ी चिंता का मुद्दा नहीं है। इसके बजाय, कई लोग घरेलू राजनीति के स्वर और राष्ट्रीय कथानक को अधिक अस्वीकार्य मानते हैं। विश्लेषकों का कहना है कि "अमेरिका अमेरिकियों के लिए है," ऐसी विचारधारा ने प्रवासी समुदायों, जिसमें भारतीय अमेरिकी भी शामिल हैं, को अलग-थलग सा महसूस कराया है।

भेदभाव और सामाजिक असंतोष की बढ़ती भावना भी इससे जुड़ी है। 2020 के बाद से सीधे हिंसा में बड़ा उछाल नहीं आया है, लेकिन लोग रोजमर्रा के पक्षपात, खासकर कार्यस्थल और ऑनलाइन पर, को लेकर चिंतित हैं। कई लोगों ने अपनी व्यवहारशैली बदल दी, कुछ बातचीत से बचे, या उन्होंने सार्वजनिक स्थानों में सुरक्षित महसूस नहीं किया। पहली पीढ़ी के प्रवासी और गैर-नागरिकों वाली समुदाय के लिए यह छोटा लेकिन लगातार असुविधा का अनुभव ही अमेरिका छोड़ने के विचार का बड़ा कारण है।

आर्थिक दबाव भी एक प्रमुख कारण है। अमेरिका में जीवन-यापन की बढ़ती लागत, विशेषकर बड़े शहरी और तकनीकी केन्द्रों में, ने कई मध्यवर्गीय परिवारों के लिए लम्बे समय तक यहां रहने को कम व्यवहारिक बना दिया है। महंगाई और नौकरी की सुरक्षा शीर्ष चिंताओं में हैं, क्रमश: 21 प्रतिशत और 17 प्रतिशत प्रतिभागियों ने इन्हें मुख्य कारण बताया। वित्तीय तनाव भारतीय अमेरिकी समुदाय के भविष्य की सोच को बदल रहा है। अब बच्चे की परवरिश की लागत 300,000 से अधिक मानी जाती है, और सैन फ्रांसिस्को, सिएटल और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में एक बेडरूम के घर का किराया 3,000 डॉलर से 5,000 डॉलर प्रति माह तक हैं।

हालांकि, अमेरिकी आप्रवास प्रणाली सबसे जटिल व लगातार चलने वाली संरचनात्मक समस्या हो सकती है। लंबी वीज़ा प्रतीक्षाओं, ग्रीन कार्ड में देरी, और नीति में अनिश्चितता ने भारतीय प्रवासी समुदाय के बड़े हिस्से को प्रभावित किया है, जिनमें कई कुशल पेशेवर अस्थायी वर्क वीज़ा पर हैं। नवीनतम वीज़ा बुलेटिन ने केवल इस धारणा को मजबूत किया है कि स्थायी निवास एक दूर का और अनिश्चित लक्ष्य है। वर्षों तथा कभी-कभी दशकों तक अमेरिका में रहने और काम करने के बावजूद, यह अस्थिरता समुदाय के बीच निराशा का मुख्य स्रोत बन रही है।

समुदाय राजनीतिक बदलाव से भी गुज़र रही है। भारतीय अमेरिकी अब किसी एक पार्टी से मजबूती से जुड़े नहीं हैं। वर्ष 2020 के बाद से, कम लोग डेमोक्रेट के रूप में पहचान कर रहे हैं, जबकि रिपब्लिकन समर्थन अधिकतर समान ही रहा है। लगभग 30 प्रतिशत लोग अब तटस्थ पहचान रखते हैं, जो लगातार बढ़ रहा है। यह पार्टी वफादारी से दूर और नौकरी की सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा और दीर्घकालिक स्थिरता जैसे व्यावहारिक मुद्दों पर आधारित निर्णय की ओर बड़े बदलाव को दर्शाता है।

तमिलनाडु ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उपलब्ध कराई गई थीं। तमिलनाडु में 17वीं विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को राज्य की सभी 234 विधानसभा क्षेत्रों में एक ही चरण में मतदान कराया गया। इस चुनाव के लिए 2.80 करोड़ पुरुष मतदाता, 2.93 करोड़ महिला मतदाता और 7,728 तीसरे लिंग सहित सहित कुल मिलाकर 5.73 करोड़ मतदाता पंजीकृत हैं।

'भारतीय व चीनी लोग जो ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

माफिया परिवारों ने मिलाकर भी नहीं किया। यह मेरी विनम्र राय है। लैपटॉप वाले गैंगस्टर। उन्होंने हमें अंधा बना दिया, हमें द्वितीय श्रेणी का नागरिक समझा, दुनिया को जीतने दिया, हमारे झंडे पर पांव रखा, आदि, आदि।"

"आपको भारत या चीन से होना चाहिए, क्योंकि लगभग सभी आंतरिक तंत्र भारतीयों और चीनी लोगों द्वारा संचालित होने के लिए बनाए गए हैं।"

सैवेज ने आरोप लगाया कि वर्तमान व्यवस्था "बर्थ टूरिज़्म" और जन कल्याण के दुरुपयोग के माध्यम से शोषित की जा रही है और तर्क दिया कि अमेरिकी संविधान आधुनिक प्रवासन के संदर्भ में पुराना हो गया है।

उन्होंने लिखा, "संविधान हवाई यात्रा से पहले लिखा गया था, टीवी से पहले, इंटरनेट से पहले, रेडियो से पहले, और आप कह सकते हैं कि जब लोग अपनी गर्भावस्था के नौवें महीने में हवाई जहाज से यहां आ रहे हैं, तो इन तर्कों की प्रासंगिकता कितनी है।"

- **ट्रंप ने पॉडकास्ट को रीपोस्ट करते हुए, भारत व चीन को पृथ्वी पर नर्क बताया।**
- **पर, अपने जोश में ट्रंप एक गलती कर बैठे, यह कहकर कि विश्व में ऐसा कोई और देश नहीं है, जो देश में जन्म लेने वाले बच्चे को ऑटोमैटिक रूप से नागरिकता प्रदान कर देता है, जबकि सच यह है विश्व में ऐसे लगभग तीन दर्ज़न देश हैं, जैसे, कैनडा, मैक्सिको आदि, जहाँ यह ऑटोमैटिक नागरिकता प्रदान करने की व्यवस्था लागू है।**

ट्रम्प ने सैवेज के नस्लवादी बयान को अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर साझा किया। इससे एक दिन पहले उन्होंने सीएनबीसी के इंटरव्यू में झूठा दावा किया कि "दुनिया का कोई देश" अमेरिका के अलावा जन्मजात नागरिकता नहीं देता। वास्तविकता यह है कि लगभग तीन दर्जन देश अपने भू-भाग पर जन्मे लोगों को स्वत: नागरिकता प्रदान करते हैं, जिनमें अमेरिका के पड़ोसी कैनडा और मेक्सिको और अधिकांश दक्षिण अमेरिकी देश शामिल हैं। ट्रम्प लंबे समय से अमेरिका में जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने की मांग करते आए हैं। जनवरी 2025 में, ओवल ऑफिस में दूसरी बार पद संभालने के बाद, ट्रम्प ने एक एग्ज़ीक्यूटिव आदेश पर हस्ताक्षर किए, जो कुछ विशेष परिस्थितियों में अमेरिका में जन्म लेने वालों को स्वत: नागरिकता दिए जाने से रोकता है।

लेकिन कानूनी रूप से व्यापक सहमति यह है कि अमेरिकी संविधान का 14वाँ संशोधन जन्मजात नागरिकता की गारंटी देता है। मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है। इस महीने की शुरुआत में, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प बनाम बारबरा मामले में तर्क सुने। इस केस में रिपब्लिकन नेता के आदेश को चुनौती दी गई है। इस मुद्दे पर आगामी निर्णय के बारे में ट्रम्प ने कहा, "यदि वे हमारे देश के खिलाफ जन्मजात नागरिकता पर फैसला करते हैं, और शायद देंगे भी, तो यह अमेरिका का भारी मात्रा में पैसा खर्च कराएगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह अमेरिका की गरिमा को नुकसान पहुंचाएगा!"

सुप्रीम कोर्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उच्च न्यायालय ने अमित जोगी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। सुनवाई के दौरान अमित जोगी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी ने कहा कि उच्च न्यायालय ने अमित जोगी का पक्ष सुने बिना ही आदेश पारित कर दिया।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908